



BACKGROUNDEERS
Press Information Bureau
Government of India

भारत के खिलौना परितंत्र को मजबूत करना

स्थानीय शिल्प कौशल से लेकर वैश्विक बाजारों तक

जुलाई 07, 2026

भारत का खिलौना उद्योग सांस्कृतिक विरासत, नवाचार और विनिर्माण विकास के एक अद्वितीय संयोग को दर्शाता है। हजारों वर्षों की विरासत के साथ, पारंपरिक खिलौने कारीगरों की मदद करते हैं, शिल्प कौशल को संरक्षित करते हैं और आजीविका को बनाए रखते हैं। युवा आबादी, बढ़ती आय और शैक्षिक खिलौनों के लिए बढ़ती प्राथमिकता के कारण मजबूत घरेलू मांग नए अवसर पैदा कर रही है। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, ओडीओपी जैसी सरकारी पहलों ने घरेलू विनिर्माण को मजबूत किया है। जीआई-टैग उत्पादों और स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के उपायों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार पहुंच को बढ़ाया है। परिणामस्वरूप, खिलौनों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है, रोजगार में वृद्धि हुई है और भारत खिलौनों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र लगातार खुद को गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से जुड़े खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

भारत का खिलौना उद्योग: उत्पत्ति से अवसर तक

भारत का खिलौना उद्योग विनिर्माण, निर्यात और नवाचार में एक जीवंत योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। अनुकूल जनसांख्यिकी, उपभोक्ता वरीयताओं को विकसित करने और निरंतर नीति समर्थन से युक्त यह क्षेत्र नई गति देख रहा है। सुरक्षित, टिकाऊ और शैक्षिक खिलौनों की बढ़ती वैश्विक मांग ने भारतीय निर्माताओं, कारीगरों और उद्यमियों के लिए नए अवसर

पैदा किए हैं। शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत के आधार पर, यह उद्योग घरेलू और वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है।

सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी की गाड़ियों से लेकर आधुनिक शैक्षिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों तक, भारत में खिलौनों की परंपरा लगभग 5,000 वर्षों से चली आ रही है। यह समृद्ध विरासत देश की रचनात्मकता, सीखने और शिल्प कौशल की स्थायी संस्कृति को दर्शाती है। इसके अलावा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से खिलौने बनाने की एक जीवंत परंपरा का पता चलता है, जो प्राचीन भारत की सरलता को प्रदर्शित करती है। कभी देश भर के गाँवों की वर्कशॉप में हाथ से बनी लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। रामायण और महाभारत से प्रेरित रंगीन गुड़िया भी इस परंपरा का हिस्सा बनीं। साथ में, उन्होंने बच्चों को देश की समृद्ध विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ा।

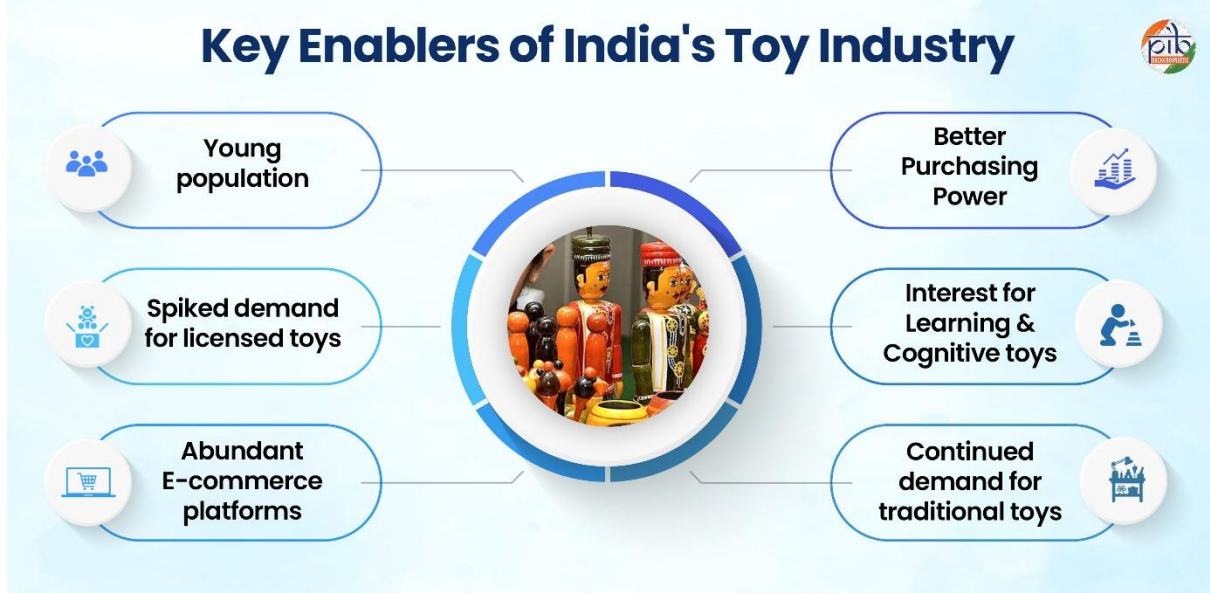
आज, पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक तकनीक, डिजाइन और उद्यमिता का सहारा मिल रहा है। यह बदलाव देश को गुणवत्तापूर्ण खिलौना निर्माण के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

भारत के खिलौना उद्योग में उभरते अवसर

आपूर्ति पक्ष पर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तेजी से विस्तार ने उत्पाद पहुंच में सुधार किया है और खिलौना निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार किया है। मांग पक्ष पर, खिलौने बनाने की भारत की समृद्ध परंपरा से निर्माताओं को एक अनूठा लाभ मिलता रहा है, जिसमें पारंपरिक खिलौने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खरीदारों को आकर्षित करते आ रहे हैं। कई कारक भारत के खिलौना उद्योग की विकास संभावनाओं को मजबूत कर रहे हैं।

- एक बड़ा और बढ़ता उपभोक्ता आधार एक प्रमुख चालक है। भारत की आबादी 1.4 अरब से अधिक है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है। बढ़ती आय और क्रय शक्ति में सुधार खिलौनों पर खर्च करने की आदत को और बढ़ा रहा है।
- तेजी से हो रहे शहरीकरण और बदलती जीवन शैली भी आधुनिक, अभिनव और लाइसेंस प्राप्त उत्पादों की मांग को बढ़ा रही है।
- माता-पिता तेजी से शैक्षिक, कौशल-आधारित और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) खिलौनों का चयन कर रहे हैं जिससे बच्चों को सीखने और उनके संज्ञानात्मक विकास में काफी मदद मिल रही है।

- प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण इस क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों को शामिल करने वाले स्मार्ट खिलौने तकनीक-प्रेमी उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।

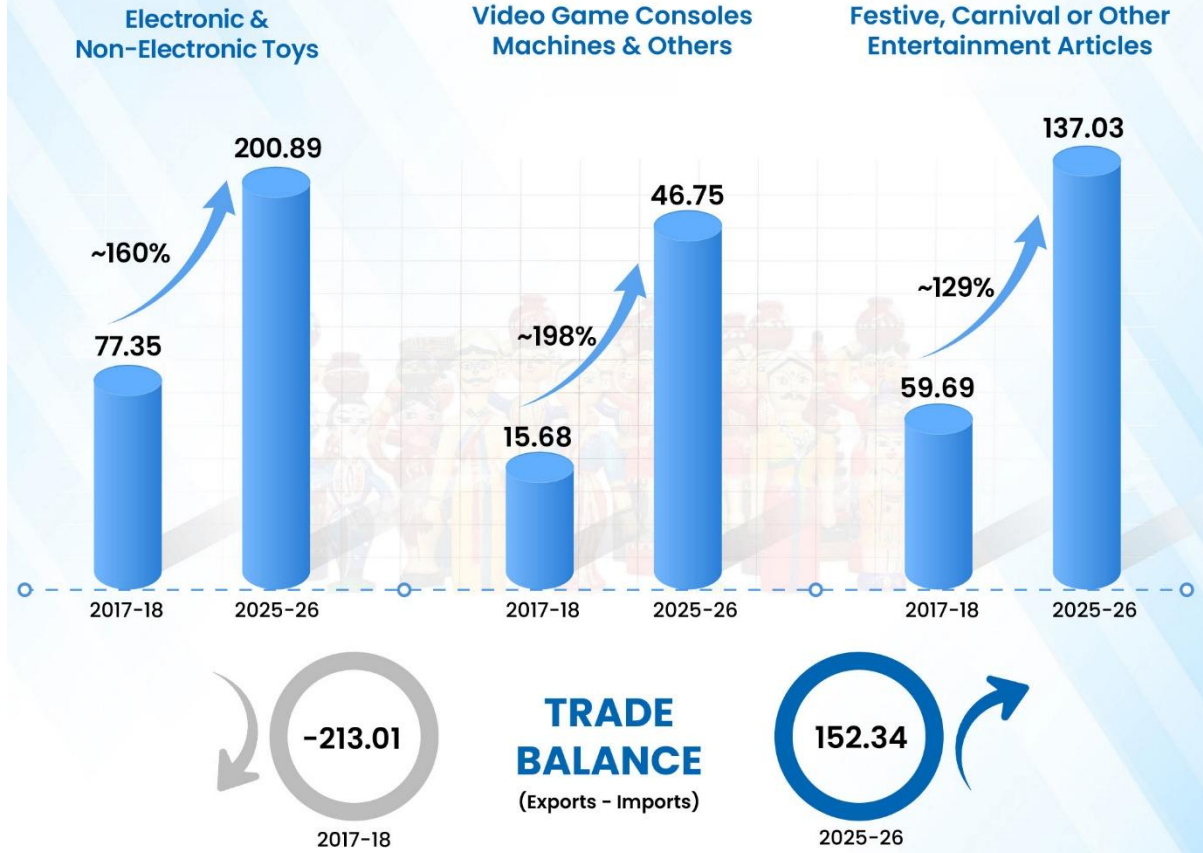


बढ़ता निर्यात, मजबूत प्रतिस्पर्धात्मकता

भारत के खिलौना उद्योग ने पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है, जो इसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और विनिर्माण क्षमताओं को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 में खिलौनों का कुल निर्यात (एचएसएन 9503, 9504 और 9505) 152.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 2025-26 में बढ़कर 384.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 151.9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण विस्तार इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों (एचएसएन 9503) में देखा गया। इसी अवधि के दौरान निर्यात में लगभग 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 77.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 200.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अमरीका अग्रणी निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा, जिसमें शिपमेंट चौगुनी से अधिक मतलब 26.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 111.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अन्य प्रमुख बाजारों में ब्रिटेन, पोलैंड, नीदरलैंड और जर्मनी शामिल थे।

TOYS DRIVING INDIA'S EXPORT STORY (in US\$ Million)



Source: Ministry of Commerce and Industry

वीडियो गेम कंसोल, मशीनों और अन्य (एचएसएन 9504) खिलौनों का निर्यात लगभग तीन गुना हो गया। यह 2017-18 में 15.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 46.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो भारत में निर्मित गेमिंग और मनोरंजक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाता है। प्रमुख देशों में संयुक्त अरब अमीरात, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है।

इसी तरह, उत्सव, कार्निवल या अन्य मनोरंजन वस्तुओं (एचएसएन 9505) का निर्यात लगभग 130 प्रतिशत बढ़ गया, जो 2017-18 में 59.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 137.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और स्वीडन इन उत्पादों के लिए अग्रणी देशों में से थे। यह वृद्धि वैश्विक उत्सव और मनोरंजन वस्तुओं के बाजारों में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है।

आयात पक्ष पर, जहां वीडियो गेम कंसोल और उत्सव तथा मनोरंजन वस्तुओं में मध्यम वृद्धि दर्ज की गई, वहीं पारंपरिक और शैक्षिक खिलौनों के आयात में 66 प्रतिशत की तेजी से गिरावट आई। इस गिरावट ने इस क्षेत्र की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को काफी मजबूत किया। परिणामस्वरूप, भारत ने 2025-26 में प्रमुख खिलौना श्रेणियों (एचएसएन 9503, 9504 और 9505) में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष हासिल किया। यह 2017-18 में दर्ज किए गए 213.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे से एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है, जब आयात निर्यात से अधिक हो गया था।

आयात से अधिक निर्यात के साथ व्यापार अधिशेष ने घरेलू विनिर्माण को मजबूत किया है, आर्थिक विकास का समर्थन किया है और विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा दिया है।

कुल मिलाकर, ये विकास विनिर्माण, रोजगार और आर्थिक विकास में खिलौना उद्योग के बढ़ते योगदान को उजागर करते हैं।

भारत के खिलौना उद्योग का आर्थिक प्रभाव

बच्चों के लिए उत्पाद बनाने के अलावा, खिलौना उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है।

यह खिलौना क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को सक्षम बनाता है और कारीगरों, निर्माताओं, व्यापारियों तथा छोटे व्यवसायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करता है। यह क्षेत्र महिलाओं और सामाजिक-आर्थिक रूप से विविध समूहों के बीच आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। स्थानीय विनिर्माण और उद्यमिता पर सरकार के ध्यान ने इस क्षेत्र के आर्थिक योगदान को और बढ़ाया है।

खेलों और खिलौनों में रोजगार (एनआईसी कोड 324) दोगुने से अधिक हो गया, जो 2018-19 में 8,685 से बढ़कर 2023-24 में 17,693 हो गया। यह देश भर में स्थानीय उद्यम विकास को बढ़ावा देते हुए उत्पादक रोजगार पैदा करने की क्षमता को दर्शाता है।

खिलौना उद्योग के भविष्य को आकार देने वाली सरकारी पहल

इस क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए, सरकार ने घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। ये प्रयास एक जीवंत वातावरण बनाने में मदद कर रहे हैं जो नवाचार, गुणवत्ता और वैश्विक बाजार उपस्थिति को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना (एनएपीटी), 2020

राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना (एनएपीटी) को भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास के आधार पर खिलौनों के डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। बच्चों में सीखने के संसाधन के रूप में खिलौनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। यह पहल खिलौनों की गुणवत्ता की निगरानी करती है और घटिया तथा असुरक्षित उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित करती है। इसके अलावा, यह स्वदेशी खिलौना समूहों को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देता है और खिलौना निर्माताओं को प्रोत्साहित करता है।

इस रणनीति का एक प्रमुख घटक 2020 में खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) की शुरुआत थी। क्यूसीओ को आयातित खिलौनों की गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में चिंताओं के जवाब में लागू किया गया था।

1. क्यूसीओ ने भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुपालन को अनिवार्य कर दिया और घरेलू और विदेशी दोनों निर्माताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

बीआईएस ने मई 2026 तक आईएस 9873/आईएस 15644 के अनुसार, खिलौनों की सुरक्षा के लिए घरेलू निर्माताओं को 1786 लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 56 लाइसेंस प्रदान किए हैं।

प्रमाणन को अनिवार्य कर दिया।

2. क्यूसीओ की वजह से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के साथ पंजीकृत कारीगरों द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले उत्पादों को छूट मिलती है।
3. यह छूट भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग वाले उत्पादों के पंजीकृत मालिकों और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को भी दी गई।

इस उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेचे जाने वाले खिलौने निर्धारित भौतिक, रासायनिक और विद्युत सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्यूसीओ के कार्यान्वयन ने घरेलू निर्माताओं के लिए समान अवसर बनाने में भी मदद की।

इस नीतिगत ढांचे के तहत, 2020 में खिलौनों पर मोस्ट-फेवर्ड नेशन (एमएफएन) टैरिफ 20 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। 2023 में यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों (एचएस 95030091) के पुर्जों पर टैरिफ को 20 प्रतिशत के रूप में संशोधित किया गया है। एमएफएन टैरिफ अधिकांश डब्ल्यूटीओ व्यापारिक भागीदारों से आयात पर लागू मानक सीमा शुल्क है। बढ़े हुए टैरिफ आयातित खिलौनों के मूल्य लाभ को कम करते हैं और घरेलू विनिर्माण तथा निवेश को प्रोत्साहित करते हैं।

इस उपाय से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलता है, खिलौना उद्योग को मजबूती मिलती है और भारत के व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

टॉय बिज़ इंटरनेशनल बी2बी प्रदर्शनी

यह प्रदर्शनी खिलौना निर्माताओं को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। देश में सबसे बड़ी खिलौना व्यापार प्रदर्शनियों में से एक के रूप में, यह व्यापार नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है। इससे निर्माताओं, खिलौना व्यापारियों और दुनिया भर के संभावित खरीदारों के बीच सीधी बातचीत भी संभव हो पाती है। यह बाजार विस्तार के अवसर पैदा करता है और वैश्विक बाजारों में भारत के खिलौना उद्योग को बढ़ावा देता है।

प्रदर्शनी 4-7 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

टॉयकैथॉन

2021 में लॉन्च की गई टॉयकैथॉन पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह छात्रों, शिक्षकों, डिजाइनरों, विशेषज्ञों और स्टार्ट-अप द्वारा अभिनव खिलौनों और खेलों के सहयोगात्मक विकास को प्रोत्साहित करती है। यह पहल भारतीय संस्कृति, विरासत, स्थानीय लोककथाओं, नायकों और मूल्य प्रणालियों से प्रेरित डिजाइनों को बढ़ावा देती है।

इलेक्ट्रॉनिक खिलौना खंड को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 2025 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकथॉन (ई-टॉयकैथॉन) का भी आयोजन किया। इस पहल में अभिनव और शैक्षिक इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का प्रदर्शन किया गया जो रचनात्मकता, सीखने और बाल विकास को बढ़ावा देते हैं।

ई- खिलौना लैब

नोएडा स्थित सी-डैक में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्थापित ई- खिलौना लैब का उद्देश्य भारत के स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक खिलौना उद्योग को मजबूत करना है। यह इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को डिजाइन करने एवं विकसित करने, प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षण में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र की पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों सहित चयनित युवा इंजीनियरों को एक वर्ष के संरचित प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है।

इस कार्यक्रम में ई- खिलौना लैब में छह महीने के शोध के साथ छह महीने का उद्योग प्रशिक्षण शामिल है। खिलौना निर्माण के साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, यह नवाचार, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी-संचालित खिलौनों के विकास को बढ़ावा देता है।

मानक मंथन

अप्रैल 2026 में, बीआईएस ने आईएस 9873 (भाग 1):2025 पर मानक मंथन का आयोजन किया। यह खिलौनों के लिए यांत्रिक और शारीरिक सुरक्षा आवश्यकताओं पर केंद्रित था। यह एक बीआईएस पहल है जिसका उद्देश्य उद्योगों में भारतीय मानकों को अपनाने को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में खिलौना निर्माताओं और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। यह बच्चों के लिए सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले और विश्वसनीय खिलौनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद)

ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से अद्वितीय उत्पादों की पहचान, ब्रांडिंग और समर्थन करके जिला-विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हुए विनिर्माण, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना है। यह घरेलू

और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नए विचारों, प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रतिस्पर्धात्मकता को भी प्रोत्साहित करता है।

इस पहल के तहत, कई पारंपरिक और स्वदेशी खिलौना उत्पादों की भी पहचान की गई है। यह उत्पाद विविधीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कौशल विकास और गुणवत्ता मानकीकरण को प्रोत्साहित करके पारस्परिक लाभ का दृष्टिकोण अपनाता है। यह ई-कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और खरीदार आवश्यकताओं तथा निर्यात प्रमाणन के बारे में जागरूकता के माध्यम से बाजार पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा, यह पहल वित्त पोषण, विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और योजना जागरूकता में सहायता करती है।

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग किए गए खिलौने

कई पारंपरिक भारतीय खिलौनों को उनकी अनूठी शिल्प कौशल और क्षेत्रीय पहचान को मान्यता देते हुए जीआई दर्जा प्राप्त हुआ है। भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग अधिक दृश्यता और बाजार पहुंच के माध्यम से कारीगरों के लिए नए अवसर पैदा करते हुए सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करने में मदद करती है। भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग किए गए उत्पादों को कानूनी सुरक्षा मिलती है, और एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उनके अद्वितीय गुणों और प्रतिष्ठा को मान्यता मिलती है। यह सुरक्षा उनके बाजार मूल्य को बढ़ाती है, अनधिकृत उपयोग को रोकती है और स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करती है। यह ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी मदद करता है। भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग किए गए खिलौनों में कर्नाटक के चन्नापटना खिलौने और गुड़िया, इंदौर, मध्य प्रदेश के चमड़े के खिलौने, तमिलनाडु की तंजावुर गुड़िया आदि शामिल हैं।

व्यापार और बाजार विकास

जीएसटी में कटौती

खिलौनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से खिलौने उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती और सुलभ हो गए हैं। यह खेल के माध्यम से बचपन की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और शैक्षिक तथा विकासात्मक खिलौनों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देता

है। इस उपाय से खिलौना बाजार में मांग को बढ़ाकर घरेलू निर्माताओं और एमएसएमई को भी लाभ होगा।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

भारत ने भारत-यूई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए), भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए), भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते, भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते और भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते जैसे व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत, भागीदार देश भारतीय खिलौनों के निर्यात के लिए बिना शुल्क बाजार पहुंच प्रदान करते हैं।

जिला निर्यात केंद्र पहल (डीईएच)

डीईएच पहल का उद्देश्य जिलों को उनके अद्वितीय उत्पादों, कौशल और संसाधनों का लाभ उठाकर निर्यात विकास केंद्रों में बदलना है। इसमें प्रमुख हितधारकों के रूप में राज्य निर्यात संवर्धन समितियां (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समितियां (डीईपीसी) शामिल हैं। इन समितियों का गठन 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इनका उद्देश्य देश के निर्यात को मजबूत करना और संतुलित समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

इस पहल ने जीआई उत्पादों, कृषि समूहों और खिलौना समूहों सहित देश भर के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की है। **खिलौना और गुड़िया निर्यात क्षमता वाले 10 से अधिक जिलों की पहचान की गई है।** यह स्थानीय उद्योगों को मजबूत करके, बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान करके, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर प्रत्येक जिले की निर्यात क्षमता का लाभ उठाता है।

भारत का खिलौना उद्योग: आगे का रुख

भारत का खिलौना उद्योग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक प्रगति के साथ सफलतापूर्वक जोड़ रहा है, जो विनिर्माण, निर्यात और रोजगार में एक जीवंत योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली पहलों की मदद से यह क्षेत्र आयात निर्भरता से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बदल गया है।

ऐसा करते हुए, भारत का खिलौना उद्योग देश की खेल की अनूठी विरासत को संरक्षित करते हुए वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है।

संदर्भ

पर्यटन मंत्रालय

https://www.cgihamburg.gov.in/pdf/press/Toy-Story-Incredible-India_23092020.pdf

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

<https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/traditional-toy-industry-new-indias-sunrise-sector>
<https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/charting-growth-story-indian-toy-industry>
<https://www.investindia.gov.in/blogs/toy-story-india-look-indias-thriving-toy-retail-market>
https://static.investindia.gov.in/s3fs-public/2025-08/2025089_v32_odop_product_list.pdf
<https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/toycathon-202-highlight-indias-toy-industry-opportunity>
<https://www.investindia.gov.in/one-district-one-product>
https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/commodity_wise_export
https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/commodity_wise_all_countries_export
<https://www.dgciskol.gov.in/writereaddata/Downloads/20251008161825A%20Brief%20Report%20on%20Indias%20Exports%20of%20Toys,%20Games%20and%20Sports%20Requisites.pdf>
<https://ipindia.gov.in/storage/uploads/docs-operator/aa9ef4c8-ae0e-477-98-52b6a9479b82.pdf>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2002099®=48&lang=2>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2244401®=3&lang=1>
https://static.investindia.gov.in/s3fs-public/inline-files/ODOP%20Brochure_Final.pdf

शिक्षा मंत्रालय

<https://isid.org.in/wp-content/uploads/2024/05/WP279.pdf?utm>

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

<https://microdata.gov.in/NADA/index.php/catalog/256/related-materials>
<https://microdata.gov.in/NADA/index.php/catalog/50/related-materials>

डीडी इंडिया

<https://www.youtube.com/watch?v=n3OZiJ7FdDc>

पीआईबी मुख्यालय

<https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=150302®=3&lang=2>

विदेश मंत्रालय

<https://www.indianembassynetherlands.gov.in/section/forthcomimg/17th-toy-biz-international-b2b-exhibition-from-4th-7th-july-2026-at-bharat-mandapam-pragati-maidan-new-delhi/>

<https://www.eoibogota.gov.in/page/6th-toy-biz-international-2025/>

इलेक्ट्रानिकी एवं आईटी मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2109677®=48&lang=2>

विश्व व्यापार संगठन

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s6p1_e.htm

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1686286®=48&lang=2>

अन्य

<https://www.ibef.org/research/case-study/unlocking-play-evolution-of-india-s-toy-sector>

https://wtocentre.iift.ac.in/PolicyBrief/Policy_Brief_23.pdf

<https://silpasathi.wb.gov.in/export-hub/>

<https://invest.telangana.gov.in/toys-industry/>

<https://x.com/mygovindia/status/205409373429240565>

<https://www.mygov.in/campaigns/aatmanirbhartoy>

<https://x.com/mygovindia/status/2054093734292410565>

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/एके/एसवी